

नज़ी संपत्तिकाे अधगिरहण पर सीमा

प्रलिमिंस के लयि:

[अनुच्छेद 39\(b\)](#) और [31C](#), [अनुच्छेद 300A](#), आर्थकि लोकतंत्र, समाजवाद, मूल अधिकार, जमींदारी प्रथा, संपत्तिका अधिकार, नौवीं अनुसूची, [अनुच्छेद 31A](#) और [31B](#), रैयतवाड़ी, नीतिनरिदेशक सदिधांत, [अनुच्छेद 14](#) और [19](#), प्रथम संशोधन अधनियिम, 1951, [अनुच्छेद 368](#), [संवधान संशोधन, संसद](#) ।

मेन्स के लयि:

स्वतंत्रता के बाद से संपत्तिकाे अधिकार का वकिास । संपत्तिकाे अधिकार को आकार देने में न्यायपालकिा की भूमकिा ।

[स्रोत: हदुस्तान टाइम्स](#)

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में प्रॉपरटी ऑनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले, 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनकि वतिरण हेतु नज़ी स्वामतिव वाले संसाधनों को अपने अधीन लेने की सरकार की शक्तिपर सीमाएँ नरिधारति की हैं ।

- याचकिाकर्त्ताओं ने तर्क दयिा कि संवधान के [अनुच्छेद 39\(b\)](#) और [31C](#) की संवैधानकि योजनाओं को आधार बनाकर राज्य द्वारा नज़ी संपत्तयिों पर कब्जा नहीं कयिा जा सकता है ।

नोट:

- [अनुच्छेद 39\(b\)](#) में प्रावधान है कि राज्य का लक्ष्य सभी के हति में भौतिक संसाधनों का वतिरण सुनशिचति करना होना चाहयि ।
- [अनुच्छेद 31C](#) के अनुसार, [अनुच्छेद 39\(b\)](#) और [39\(C\)](#) को समानता के अधिकार ([अनुच्छेद 14](#)) या [अनुच्छेद 19](#) के तहत अधिकारों (अभविक्त्तिकाे स्वतंत्रता, शांतपूरवक एकत्र होने का अधिकार आदि) का हवाला देकर चुनौती नहीं दी जा सकती है ।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मुख्य नषिकर्ष क्या हैं?

- नज़ी संसाधनों का अधगिरहण:** जो संसाधन दुर्लभ हैं या सामुदायकि कल्याण के लयि महत्त्वपूरण हैं, उन्हें राज्य अधगिरहण के लयि योग्य माना जाना चाहयि, न कि सभी नज़ी संपत्तयिों को ।
 - "सार्वजनकि ट्रस्ट सदिधांत" (जहाँ राज्य द्वारा जनता के लयि कुछ संसाधनों को ट्रस्ट में रखा जाता है) सेइस नरिधारण का मार्गदर्शन हो सकता है ।
- संसाधन योग्यता के लयि परीक्षण:** न्यायालय ने दो प्रमुख परीक्षण नरिधारति कयिे हैं अर्थात संसाधन "भौतिक" और "समुदाय से संबंधति या उसका कल्याण करने वाले या दोनों होने चाहयि ।
 - नज़ी स्वामतिव वाले संसाधन और उसके सामुदायकि तत्त्व की भौतिकता का मूल्यांकन वषियगत आधार पर कयिा जाना चाहयि ।
 - भौतिकता से तात्पर्य भूमि, खनजि या जल जैसी परसंपत्तयिों के आर्थकि, सामाजकि और पर्यावरणीय गतशीलता पर पड़ने वाले प्रभाव से है ।
- रंगनाथ रेड्डी मामले, 1977 के वपिरीत नरिणय:** बहुमत द्वारा [\[1977\] 2 SCR 1013](#), 1982 [\[1982\] 2 SCR 1013](#) पलट दयिा गया, जसिमें [\[1977\] 2 SCR 1013](#), 1977 में दएि गए तर्क को बरकरार रखा गया था कि सभी नज़ी संपत्तयिों को पुनर्वतिरण हेतु "समुदाय के भौतिक संसाधन" माना जा सकता है ।
 - एकमात्र असहमति जताने वाले न्यायमूरत्सिुधांशु धूलयिा ने समुदाय के "भौतिक संसाधनों" को परभाषति करने में व्यापक वधिायी वविकाधिकार की वकालत की ।

- अनुच्छेद 39(b) पर प्रतर्बिंध: न्यायालय ने अनुच्छेद 39(b) की व्यापक व्याख्या के प्रतर्बिंध कथित किया, जिससे अनुच्छेद 300A के तहत संपत्तिकाे अधिकार पर प्रतर्बिंध प्रभाव होगा।
 - अनुच्छेद 300A: किसी भी व्यक्तिकाे कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्तिकाे वंचित नहीं किया जाएगा।
- नजिकाे संसाधनकाे सामुदायिकाे संसाधनकाे बदलना: सर्वोच्च न्यायालय ने नजिकाे संसाधनकाे सामुदायिकाे भौतिकाे संसाधनकाे बदलने के पाँच तरीके बताए हैं:
 - राष्ट्रीयकरण, अधगिरहण, वधिकाे कर्षान्वयन, राज्य द्वारा खरीद और संपत्तिकाे मालिकाे द्वारा दान।

संपत्तिकाे अधिकार से संबधति संवैधानिकाे प्रावधान क्या हैं?

- अनुच्छेद 31: अनुच्छेद 31 (एक मूल अधिकार) संपत्तिकाे अधिकार से संबधति था, लेकिन इसे नरिस्त कर दिया गया (44वें संशोधन अधनियिम, 1978) और अनुच्छेद 300A (संवैधानिकाे अधिकार) द्वारा प्रतर्बिंध कथित किया गया।
 - प्रथम संशोधन अधनियिम, 1951: प्रथम संशोधन अधनियिम, 1951 द्वारा संवैधानिक में अनुच्छेद 31A और 31B के साथ -साथ नौवीं अनुसूचा भी शामिल की गई।
 - अनुच्छेद 31A: इसने राज्य को मूल अधिकारकाे के साथ असंगतिकाे आधार पर चुनौती दयि बना संपत्तिकाे अर्जति करने या संपत्तिकाे में अधिकार में परिवर्तन की शक्तिकाे प्रदान की।
 - अनुच्छेद 31B: यह सुनिश्चित करता है कि नौवीं अनुसूचा में शामिल कानूनकाे को रद्द नहीं किया जा सकेगा, भले ही वे मूल अधिकारकाे के वरिद्ध हों।
 - नौवीं अनुसूचा: इसमें केंद्रीय और राज्य कानूनकाे की सूचा शामिल है जनिहें न्यायालयकाे में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसेभूमिकाे सुधार कानून।
- 25वां संशोधन अधनियिम, 1971: इसने अनुच्छेद 39(B) एवं (C) के तहत संसाधन वतिरण के उद्देश्य से राज्य के कानूनकाे को संवैधानिकाे चुनौतिकाे से बचाने के लयि अनुच्छेद 31C जोड़ा गया।
 - संशोधन ने अदालतकाे को राज्य के कार्याकाे की समीक्षा करने से रोक दिया, भले ही वे मनमाने या तर्कहीन हों।
- 42वां संशोधन अधनियिम, 1976: इसने सभी नदिशक तत्त्वकाे को शामिल करने के लयि अनुच्छेद 31C के दायरे का वसितार कथित।
 - यह प्रावधान योग्य कानूनकाे को अनुच्छेद 14 एवं 19 के तहत नरिस्त होने से बचाता है यदयि वास्तव में संसाधन पुनर्वतिरण के माध्यम से सार्वजनिकाे कल्याण सुनिश्चित करते हैं।
- 44वां संशोधन अधनियिम, 1978: अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31, जो संपत्तिकाे अर्जति एवं धारण करने के साथ-साथ नपिटान करने के अधिकार की रक्षा करते थे, को नरिस्त कर दिया गया, जिसका अर्थ है कि इसने संपत्तिकाे अधिकार को मूल अधिकारकाे की सूचा से हटा दिया।
 - भाग XII के अध्याय IV में अनुच्छेद 300A के अंतर्गत संपत्तिकाे एक संवैधानिकाे अधिकार के रूप में स्थापति हुआ।

संपत्तिकाे अधिकार से संबधति न्यायिकाे व्याख्या क्या है?

- 1951: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम संशोधन अधनियिम, 1951 को बरकरार रखा, जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक में संशोधन करने के लयि संसदीय वशिषाधिकार की पुष्टिकाे की गई और साथ ही यह नरिणय दिया गया कि मौलिकाे अधिकारकाे को प्रभावति करने वाले संशोधन अनुच्छेद 13(2) द्वारा प्रतर्बिंधति नहीं हैं।
 - अनुच्छेद 13(2) न्यायिकाे समीक्षा का प्रावधान करता है जो मौलिकाे अधिकारकाे के साथ टकराव करने वाले कानूनकाे को अमान्य घोषति करने में सहायता प्रदान करता है।
- 1954: सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि अनविार्य संपत्तिकाे अधगिरहण के मामलाे में सरकार को उचित मुआवजा प्रदान करना आवश्यक है।
- 1973: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कथित कि संवैधानिकाे संशोधन अनुच्छेद 13(2) के प्रतर्बिंधकाे के अधीन नहीं है, जिसका अर्थ है कि संसद, संवैधानिक में संशोधन कर सकती है, जिसमें संपत्तिकाे अधिकार से संबधति प्रावधानकाे में परिवर्तन करना या समाप्त करना शामिल है।
- 1980: सभी नदिशक सदिधांतकाे को शामिल करने के लयि अनुच्छेद 31C के दायरे का वसितार करने काे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारजि कर दिया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31C की न्यायिकाे जाँच को रोकने वाले प्रावधानकाे को भी नरिस्त कर दिया, परिणामस्वरूप संवैधानिकाे जाँच और संतुलन के सदिधांत को बल मलित।
- 1981: यह माना गया कि केशवानंद भारती मामलाे से पहले नौवीं अनुसूचा में संवैधानिकाे संशोधन और कानून न्यायिकाे चुनौती से संरक्षति हैं।
 - हालाँकि, इन मामलाे के बाद जोड़े गए संशोधन मूल संरचना सदिधांत के आधार पर न्यायिकाे समीक्षा के अधीन हैं।
- 2020: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बिना उचित प्रकरया के किसी व्यक्तिकाे नजिकाे संपत्तिकाे को जबरन बेदखल करना मानवाधिकारकाे और अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिकाे अधिकार दोनकाे का उल्लंघन है।

सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय का महत्त्व क्या है?

- राज्य एवं व्यक्तगित अधिकार: यह राज्य के हस्तक्षेप की संभावना को संरक्षति करता है, जबकि यह स्वीकार करता है कि नजिकाे संसाधनकाे का अंधाधुंध अधगिरहण स्वीकार्य नहीं है।

- **आर्थिक लोकतंत्र:** यह नरिणय डॉ.बी.आर.अंबेडकर के "आर्थिक लोकतंत्र" के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो यह सुनिश्चित करता है कि संविधान एक कठोर आर्थिक संरचना को नरिदेशति नहीं करता है, इस प्रकार लोगों की अपने सामाजिक एवं आर्थिक संगठन का नरिणय लेने की स्वतंत्रता को संरक्षति करता है।
- **लचीली/नमय व्याख्या:** इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि अनुच्छेद 39(B) जैसे नरिदेशक सदिधांतों को इस तरह से करयान्वति कयिा जाना चाहयिे जो वकिसशील सामाजिक और आर्थिक वास्तवकताओं को प्रतबिबिति करे, न कि कसिी एक कठोर आर्थिक सदिधांत को।
- **वधियी ढाँचा:** यह नरिणय आर्थिक और कल्याणकारी नीतयिों को आकार देने में नरिवाचति सरकारों और लोकतांत्रिक प्रकरयिा की भूमिका को पुष्ट करता है।
- **कल्याण:** भवषिय की कल्याणकारी नीतयिों संभवतः सार्वजनिक कल्याण के लयिे आवश्यक दुर्लभ, महत्त्वपूर्ण संसाधनों पर केंद्रति होंगी। राज्य प्रगतशील कराधान और सार्वजनिक योजनाओं जैसी अधिक लक्षति कल्याणकारी रणनीतयिों अपना सकता है।

संपत्ति पर राज्य के नरियंत्रण का प्रभाव क्या है?

- **सकारात्मक प्रभाव:**
 - **न्यायसंगत पुनर्रवतिरण:** हाशएि पर पड़े समूहों में संसाधनों का पुनर्रवतिरण करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है तथा धन असमानता को कम करता है।
 - **संसाधन प्रबंधन:** यह सुनिश्चित करता है कि भूमि, जल और खनजि जैसे संसाधनों का उपयोग स्थायी रूप से और सार्वजनिक लाभ के लयिे कयिा जाए।
 - **लोक कल्याण संबंधी परयोजनाएँ:** सार्वजनिक उद्देश्यों के लयिे भूमि या संपत्ति का अधगिरहण करके बुनयिादी ढाँचे के वकिस, सवास्थय देखभाल और शकिसा की सुवधिा प्रदान करती हैं।
 - **कमज़ोर समूहों की सुरक्षा:** वंचति समुदायों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है।
- **नकारात्मक प्रभाव:**
 - **नजिी स्वामतिव पर सीमाएँ:** व्यक्तगित संपत्ति अधिकारों को कम करती है, जसिसे नजिी नविश एवं उद्यमशीलता को हतोत्साहति होने की संभावना होती है।
 - **प्रोत्साहन में कमी:** राज्य के प्रतबिंधों के कारण नजिी मालकों में संपत्ति में सुधार या नविश करने हेतु प्रोत्साहन में कमी हो सकती है।
 - **आर्थिक स्थरिता:** अत्यधिक वनियमन या अत्यधिक नरियंत्रण बाज़ार-संचालति वकिसा एवं नवाचार को बाधति कर सकता है।

नषिकर्ष

2024 के नरिणय ने नजिी संपत्ति के अधगिरहण के लयिे राज्य की शक्ति के बारे में महत्त्वपूर्ण मसाल कायम की है। यह सार्वजनिक उद्देश्य, मुआवज़ा और मामले-दर-मामले आकलन की आवश्यकता पर बल प्रदान करता है, और साथ ही व्यक्तगित संपत्ति अधिकारों को सामान्य हति के साथ संतुलति भी करता है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: वभिनिन ऐतहिसिक मामलों में संपत्ति के अधिकार की न्यायिक व्याख्या पर चर्चा कीजिये।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

2021

प्र. भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थति है? (2021)

- केवल नागरिकों के लयिे उपलब्ध वधिक अधिकार
- कसिी भी व्यक्त के लयिे उपलब्ध वधिक अधिकार
- केवल नागरिकों के लयिे उपलब्ध मौलिक अधिकार
- न तो मौलिक अधिकार और न ही कानूनी अधिकार

उत्तर: (b)

2016

प्रश्न. कोहलिो केस में क्या अभनिरिधारति कयिा गया था? इस संदर्भ में क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्रवलोकन संविधान के बुनयिादी अभलिकषणों में प्रमुख महत्त्व का है? (2016)

प्रश्न: कृषिविकास में भूमिसुधारों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। भारत में भूमिसुधारों की सफलता के लिये उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिये। (2016)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/limit-on-private-property-acquisition>

